मुख्य सचिव

प.सं: 1823/प्र.नि.स.–मु.स./2021
दिनांक: 11 नवम्बर, 2021

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

विभिन्न विभागों से सम्बन्धित मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में दायर की गयी रिट याचिकाओं के अन्तर्गत बहुधा यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार को पक्षकार जरिये मुख्य सचिव बनाया जा रहा है और इस कारण राज्य सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र दायर किए जाने हेतु मुख्य सचिव से पूर्व अनुमोदन/प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु पत्रावलियां प्रस्तुत हो रही हैं।

2. उक्त के सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत **Office Memorandum No. 75/UC/Institution Section/ 2021** दिनांक 08 नवम्बर, 2021 **(छायाप्रति संलग्न)** अत्यन्त प्रासंगिक है जिसमें मा. उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि राज्य सरकार से सम्बन्धित विषयों में सम्बन्धित विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होने के कारण याचिका में राज्य सरकार को सम्बन्धित विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव के माध्यम से पक्षकार बनाया जाना चाहिए न कि मुख्य सचिव के माध्यम से।

3. अतएव, कृपया मा. उच्च न्यायालय की उक्त अवधारणा के आलोक में आपके प्रभाराधीन विभाग/विभागों से सम्बन्धित रिट याचिकाओं में से जिनमें राज्य सरकार को पक्षकार मुख्य सचिव के माध्यम से बनाया गया है, उनमें राज्य सरकार की ओर से मा. उच्च न्यायालय में अविलम्ब प्रार्थना पत्र/प्रतिशपथ पत्र दायर करते हुए मुख्य सचिव के स्थान पर सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), यथा लागू, को प्रतिस्थापित कराना सुनिश्चित कर लिया जाय। इसी प्रकार, जिन मामलों में राज्य सरकार के लिए पारित किए गए निर्णय का अनुपालन न किए जाने के आधार पर मुख्य सचिव के विरूद्ध अवमानना याचिका दाखिल की गयी हों, उनमें भी मुख्य सचिव की ओर से दायर किए जाने वाले प्रतिशपथ पत्र/उत्तर में मा. उच्च न्यायालय की उक्त अवधारणा (**Office Memorandum** दिनांक 08 नवम्बर, 2021) का भी अवश्य आधार उल्लिखित किया जाय।

संलग्नक : यथोक्त.

(डॉ. एस. एस. संधु)
मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया राज्य सरकार को मुख्य सचिव के माध्यम से पक्षकार बनाये गये सभी प्रकरणों (रिट याचिकाओं) का विवरण शीघ्रातिशीघ्र सम्बन्धित विभाग के प्रमुख के साथ–साथ मेरे कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

1. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

(डॉ. एस. एस. संधु)
मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन, 4 सुभाष मार्ग, देहरादून, दूरभाष : (0135) 2712100, 2712200 फैक्स : 2712500
E-Mail : cs-uttarakhand@nic.in , chiefsecyuk@gmail.com

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

OFFICE-MEMORANDUM

No. 75/UHC/Institution Section/2021 Dated 08.11.2021

SUB: IMPLEADMENT OF CHIEF SECRETARY TO THE STATE GOVERNMENT IN MATTERS FILED AGAINST THE STATE.

On the subject above, kind attention of all the members of the Bar is invited to some matters, particularly the Writ Petitions, being filed in the Hon'ble High Court, where, State is being made the respondent through Chief Secretary to the Government.

2 In this regard, I am directed to say that the members of the Bar will agree that though Chief Secretary to the Government is head of the State Secretariat, but none of the department of the Government comes under his portfolio. In fact, the Secretaries/Principal Secretaries to Government are the portfolio Secretaries of their respective departments. Thus, they look after all the affairs of their departments. Further, matters relating to the litigation involving the State are looked after only by concerned departments, and not by office of the Chief Secretary. The members of the Bar will also agree that as per the practice and procedure rules also, State should be impleaded only through the Secretary/Principal Secretary of the concerned department.

3 In view of the above, I am directed to request all the members of the Bar that in all matters, where State is impleaded as a party, the State should be impleaded only through the Secretary/Principal Secretary of the concerned Department.

By Orders of Hon'ble the Chief Justice

Sd/-
Registrar General

No. 5307/UHC/Institution Section/2021, Dated 08.11.2021

1. P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice for placing copy of this Office Memorandum before His Lordship.
2. Private Secretaries to the Hon'ble Judges, for placing copy of the Office Memorandum before Their Lordships.
3. Private Secretary to the Advocate General, Uttarakhand.
4. Chief Standing Counsel/Government Advocate, Uttarakhand.
5. Assistant Solicitor General for Government of India at Nainital.
6. Additional Chief Standing Counsel for State of Uttar Pradesh at Nainital.
7. President/Secretary, High Court Bar Association, Nainital with request to inform all the members of the Bar.
8. Private Secretary to the Registrar General.
9. All the Registrars/JRs/DRs/ARs of the Hon'ble Court.
10. All the Sections of the Hon'ble Court.
11. Computer Section with request to upload a copy of this Office Memorandum in the official website of the Hon'ble Court.
12. Guard file/Notice Board.

Registrar (Judicial)